प्रेषक.

अतर सिंह संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादूनः

दिनांकः 06जुलाई, 2016

विषय— वित्तीय वर्ष 2016—17 के लेखानुदानों के अन्तर्गत राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालनार्थ लेखानुदान के माध्यम से प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—5प/1/25/2016—17/13633 दिनांक 23जून, 2015 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31.04.2016 व शासनादेश संख्या—504/XXVII(1)/2016 दिनांक 04.04.2016 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016—17 के प्रथम चार माह हेतु पारित/स्वीकृत लेखानुदानों के अन्तर्गत आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या—12 के लेखाशीर्षक —2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के आयोजनागत पक्ष में ₹63.33 लाख (रूपये तिरसठ लाख तैतीस हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में शहरी क्षेत्रों में कियाशील चिकित्सालयों हेतु ₹1000.00 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों हेतु ₹500.00 लाख इस प्रकार कुल ₹1563.33 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख तैतीस हजार मात्र) संलग्न अलॉटमेंट आई०डी० के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

- 1. बजट नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष में शहरी क्षेत्रों में कियाशील चिकित्सालयों के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि ₹1000.00 लाख में से ₹200.00 लाख दून मेडिकल कॉलेज,देहरादून (पूर्ववर्ती राजकीय दून चिकित्सालय,देहरादून) के लिए अवमुक्त किया जायेगा।
- 2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—पांच भाग—1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग—1 के सुसंगत शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—490 / XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जाय, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायें, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
- 8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—12 के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—1080/XXVII(1)/2015 दिनांक 08 सितम्बर,2015 एवं शासनादेश संख्या—490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31.03.2016 के आलोक में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : ऑन लाईन एलॉटमेन्ट आई.डी. S1607120021

भवदीय, (अंतर सिंह) संयुक्त सचिव

संख्या- 800 (1)/XXVIII-5-2016-46/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
- 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड,देहरादून।
- 3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहराद्न।
- 4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन०आई०सीø।
- 7. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह) संयुक्त सम्बद